Sl. No.	Locations	No. of ITIs
37	Jankara	1
38	Khambhat	2
39	Kadi	1
40	Thasra	1
41	Dholka	1
42	Umreth	1
43	Veramal	1
44	Dhurmaj	1
45	Atarsumba	1
46	Vapi	1
47	Dabrow	1
48	Dhansura	1
49	Madangarh	1
50	Vasma	1
51	Mansa	1
52	Kalki	1
53	Vadukal	1
54	Tankaria	1
55	Kutch	1
56	Khambholaj	1
57	Baroda	2
58	Paten	1
59	Chanasma	1
60	Mangrol	1
61	Narpetlod	1
62	Velpura	1
63	Dharamdacha	1
64	Dabhoi	1
65	Halol	1
66	Kapoolganj	1
	TOTAL :	32
67	Sanad	1
68	Jam Nagar	1
69	Mehsana	1
70	Palej	1
71	Vagara	1
72	Ishvaram Nagar	1
	TOTAL :	38
	GRAND TOTAL :	77

Industrial dispute between the Management and workers of JCT Electronics

3249. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an industrial dispute between the management and worker of JCT Eleotrosics, Mohali District Roper, Punjab;

(b) whether it is also a fact that the employees of the company were kidnapped, kept under illegal custody and were manhandled by the management;

(c) if so, whether any of these emp loyees succumbed to injuries inflicted on them: and

(d) what action Government propose to take against the management?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (b) According to the information furnished.

by the Government of Punjab, the workers of the enterprise raised an indilst-rail dispute over disciplinary action taken against three women which resulted in their dismissal from service on August, 31, 1991. The industrial dispute was amicably settled between the manage-. ment and the workmen in November, 1991.

It had been alleged by the workers' union that on September 27, 1991 a worker was kidnapped and manhandled by the management and later released by them- The worker has filed a complaint in the Court of a Judicial Magist. rate. No FTR was, however, lodged the police.

उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय

3250 **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं ; और

(ख) 30 जून, 1991 को इन श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हुए थे तथा कितने मामलों का कर्मचारियों के हित में फैसला हुआ और ये कितने समय से लंबित थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवर) : (क) उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 19 श्रम न्यायालय तथा 6 औद्योगिक अधिकरणों का गठन किया है औ: केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय सरकार औद्योगिक-अधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उसके द्वारा गठित विभिन्न श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में 12,075 औद्योगिक विवाद तथा 5,095 आवेदन लंबित हैं । कानपुर स्थित केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में 741 औद्योगिक विवाद और 886 आवेदन लंबित हैं । जितनी अवधि के लिए ये मामले लंबित हैं वह नीचे दी गई है :—

अवधि	केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण तथा श्रम-न्यायालय, कानपुर		उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण	
	औद्योगिक विवाद	आवेदन	औद्योगिक विवाद	आवेदन
एक साल से कम	622	710	5184	2548
1 से 2 साल के बीच	42	10	3439	1281
2 से 3 साल के बीच	63	152	1967	699
3 साल से अधिक	14	14	1485	567